Concern over unprecedented decline in school enrolment

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) **:** मान्यवर, यह सरकार बहुप्रचारित 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देकर आई थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टी है। शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, UDISE रिपोर्ट के अनुसार पहली बार स्कूल नामांकन के आँकड़े 2022-23 में 25.17 करोड़ तक गिर गए, 2023-24 में और भी कम होकर ये 24.8 करोड़ हो गए। यह 2018-19 से 2021-22 की अवधि की तुलना में लगभग 1.55 करोड़ छात्र, जो लगभग 6 प्रतिशत है, इस गिरावट को दर्शाता है। यह रिपोर्ट इस बात पर सवाल उठाती है कि मोदी सरकार भारत के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में किस तरह विफल हुई है। यह गिरावट केवल एक नंबर नहीं है, यह बढ़ती आर्थिक असमानता और आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाती है, जो गरीब परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने बताया कि उनके स्कूल के कमरे कम उपयोग में हैं।
जबकि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य अत्यधिक बोझ और बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं। यह सिर्फ संख्या में कमी नहीं है, बल्कि यह एक पीढ़ी की शिक्षा तक पहुंच को खोने का मामला है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसलिए आंकड़े चेतावनी देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार अपने निर्धारित कामों को प्राथमिकता देगी या प्रचार और छवि निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी लेगी?

मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि सरकार स्कूल नामांकन के आंकड़े में गिरावट के मामले में स्पष्टीकरण दे। ये कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और फिर इसका बजट भी कम कर दिया यानी ये शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं हैं। सच्चाई यह है कि ये शिक्षित बेरोजगार नहीं पैदा करना चाहते हैं। ये उनको शिक्षा ही नहीं देना चाहते, जिससे वे सरकार से पूछ सकें कि हमारे अधिकार क्या हैं। ये बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं। आज रिकॉर्ड बेरोजगारी हो रही है, इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : विषय महिलाओं पर नहीं है। विषय स्कूल में enrolment का है।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, क्या स्कूल में महिलाएं नहीं पढ़तीं?

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलें। आप खुद अनुभवी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, मैं सिर्फ विषय पर बोल रहा हूँ। मैंने आज यही नोटिस दिया है।

श्री उपसभापति : बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी : आप मेरा नोटिस देख लें।

श्री उपसभापति : ठीक है, बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, हमारे देश में आदिवासी वर्ग की महिलाओं और बच्चों के ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपका विषय enrolment पर है।

श्री प्रमोद तिवारी : मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको क्यों रोका जा रहा है? ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : तिवारी जी, विषय enrolment पर है। अब आप बैठ जाएँ।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : उपसभापति महोदय, मैं on record इस बात को clear करना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य एक बहुत सीनियर एमपी हैं। उन्होंने एक बात कही कि हमने बजट घटा दिया। इतिहास से लेकर अब तक, बजट में एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा आबंटन, इस बार के बजट में हुआ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Pramod Tiwari : Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Sanjay Singh (National Capital Territory of Delhi), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Smt. Sagarika Ghose (West Bengal), Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh) and Smt. Jebi Mather Hisham (Kerala).

Shrimati Jebi Mather Hisham. Concern over negative impact of deep-sea mineral exploration and mining along the Kerala coast.

Concern over the negative impact of deep-sea mineral exploration and mining along the Kerala coast

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I rise today to address a very grave issue. It is the survival of our fishing community, especially the fishermen of Kerala, who are under serious threat. The Central Government has announced deep-sea